



Dynamic वदित से बढी भारत की अहमयित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि देश की वदित नीति राष्ट्रीय हति से नरिदेशति होती है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जा रही है। भारत की वदित नीति ऐसी है जिसमें वैश्विक संतुलन कायम रखते हुए सभी देशों से बेहतर संबंध बनाने पर जोर दिया जाता है। भारत अन्य देशों के साथ समय-समय पर वभिन्न कषेत्रों में वभिन्न मुद्दों पर समझौते करता रहता है। हाल ही में भारत ने अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग वषियों पर कुछ समझौते किये हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के कषेत्र में भारत-फ्रांस MoU

इस MoU के तहत भारत और फ्रांस का लक्ष्य आपसी लाभ, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर तकनीकी द्वपिकषीय सहयोग को बढावा देने के लिये सहकारी संस्थागत संबंध सुनश्चिति करने का ठोस आधार स्थापित करना है। इसके अलावा अनुसंधान से जुड़े संयुक्त कार्यदल, प्रायोगिक (Pilot) आधार पर चलाई जाने वाली परियोजनाएँ, कषमता नरिमाण कार्यक्रम, अध्ययन भ्रमण (Study Tour), केस स्टडी और अनुभव एवं वषिषज्जता को साझा करने के कार्य तकनीकी सहयोग के दायरे में आएंगे।

समुद्री मुद्दों पर भारत-डेनमारक समझौता

इस समझौते से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग के कषेत्रों का पता लगाने में आसानी होगी। भारत और डेनमारक के समुद्री कषेत्रों के मध्य सीमा-पार सहयोग और नविशों में मदद करना इस समझौते का एक अहम हसिसा है। इस समझौते में दोनों देशों को बेहतर जहाज़रानी (Quality Shipping) सुवधिएँ सुनश्चिति करने हेतु आपसी कषमताओं को सुधारने के लिये वषिषज्जों, प्रकाशनों, सूचना, डेटा और सांख्यिकी का आदान-प्रदान करने के प्रावधान किये गए हैं। इसके अलावा यह समझौता हरति समुद्रीय प्रौद्योगिकी एवं शपि-बलिडगि के कषेत्र में सहयोग, भारत के शपिगि पंजीयक को मान्यता प्राप्त संगठन का दर्जा प्रदान करने तथा समुद्री प्रशकषण और शकषा के कषेत्र में सहयोग करने में समर्थ बनाएगा। **इस समझौते से मर्र्चेंट शपिगि और समुद्रीय परविहन संबंधति मामलों के कषेत्र में सतत सहयोग के लिये अनुसंधान और वकिस को भी गति मिलेगी।**

भारत-जापान द्वपिकषीय वनिमिय व्यवस्था

भारत और जापान के बीच द्वपिकषीय वनिमिय व्यवस्था (Bilateral Swap Agreement) के लिये समझौता कया गया है। इसके लिये भारतीय रज़िर्व बैंक को बैंक ऑफ जापान और भारतीय रज़िर्व बैंक के मध्य द्वपिकषीय वनिमिय व्यवस्था के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु अधकृत कया गया। यह वनिमिय व्यवस्था वदिशी मुद्रा में अल्पकालिक कमी को पूरा करने के लिये भुगतान संतुलन के उचित स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से घरेलू मुद्रा के अधकितम 75 बलियिन अमेरिकी डॉलर के आवश्यक वनिमिय और पुनर्वनिमिय के लिये भारत और जापान के मध्य एक अनुबंध है।

द्वपिकषीय वनिमिय व्यवस्था के तहत परेशानी के समय एक-दूसरे की मदद करने के रणनीतिक उद्देश्य की पूर्तति होगी। इस सुवधि से भारत को उपयोग के लिये पूंजी तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। इस व्यवस्था से भारतीय कंपनियों के लिये वदिशी पूंजी की नकिसी की संभावनाओं में सुधार आएगा, क्योंकि देश की वनिमिय दर में अधक सथरिता आएगी। भुगतान संतुलन (Balance of Payment) में उत्पन्न होने वाली कठनाइयों से नपिटने में ऐसी वनिमिय व्यवस्था की उपलब्धता से घरेलू मुद्रा पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और वनिमिय दर की असथरिता से नपिटने के लिये भारतीय रज़िर्व बैंक की कषमता में वृद्धि होगी।

एडवांस मॉडल सगिल वडि के वकिस पर भारत-जापान MoU

इस MoU से कारोबार से जुड़े कार्यों हेतु आवश्यक प्रशासनिक प्रकरियाओं के लिये 'उन्नत मॉडल एकल खडिकी' (Advance Model Single Window) के वकिस और भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस पर अमल किये जाने से भारत और जापान के बीच सहयोग सुनश्चिति होगा। इसके साथ ही एक ऐसे ढाँचे के वकिस के लिये भी दोनों देशों के बीच सहयोग संभव होगा जिसमें ये प्रकरियाएँ त्वरति ढंग से पूरी होंगी। इससे देश में 'कारोबार में सुगमता' को बढावा देने के लिये भारत द्वारा कयि जा रहे प्रयासों में तेज़ी आएगी। 'उन्नत मॉडल एकल खडिकी' भारत में और इससे बाहर अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तौर-तरीकों या प्रथाओं पर आधारित है। इसमें मापने योग्य पैमाने या मापदंड भी हैं और इससे भारत में 'एकल खडिकी' की स्थापना के मार्ग में आने वाली संभावति बाधाओं की पहचान हो सकेगी। अतः इससे नविश करना सुवधिजनक हो जाएगा।

स्वाजीलैंड को कर संबंधी सहायता के लिये ToR

भारत और स्वाजीलैंड (नया नाम एस्वातनी-Eswatini) के बीच सीमा वहीन कर नरीक्षक कार्यक्रम (Tax Inspectors Without Borders Programme-TIWPB) के तहत स्वाजीलैंड को कर संबंधी सहायता देने के लिये नामति भारतीय वशिषज्ज की सहभागिता से संबंधति वचिरार्थ वषिय (Terms of Reference-ToR) पर हस्ताक्षर कयि गए हैं। इसके लिये भारत और एस्वातनी सरकार द्वारा एक भारतीय वशिषज्ज को पारस्परिक सहमतिसे चुना गया है। इससे सीमा वहीन कर नरीक्षक कार्यक्रम के तहत एस्वातनी को कर-संबंधी सहायता देने के लिये नामति भारतीय वशिषज्ज की सहभागिता से जुडी शर्तों को औपचारिक रूप दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय वशिषज्ज की सहभागिता से विकासशील देशों में कर संबंधी मामलों में क्षमता नरिमाण करने में भारत द्वारा सहयोग को बढ़ावा मलिगा।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme-UNDP) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू कयि गए TIWPB का उद्देश्य ऑडिट क्षमता के सुदृढीकरण के ज़रयि राष्ट्रीय कर प्रशासन को मज़बूत करने के लिये विकासशील देशों को आवश्यक सहयोग देना और अन्य देशों के साथ इस जानकारी को साझा करना है। TIWPB का उद्देश्य विकासशील देशों के टैक्स ऑडिटिरो को आवश्यक तकनीकी जानकारयिओ और कौशल हस्तांतरति करने के साथ-साथ इन टैक्स ऑडिटिरो के साथ सामान्य ऑडिटि प्रथाओ और ज्ञान संसाधनों के प्रचार-प्रसार को साझा करके इन देशों के कर प्रशासनों को मज़बूत करना है। TIWPB कर संबंधी मसलों पर सहयोग बढ़ाने के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा कयि जा रहे प्रयासों का पूरक है और साथ ही यह विकासशील देशों के घरेलू कर जुटाने संबंधी प्रयासों में भी योगदान करता है। भारत विकासशील देशों में कर संबंधी मसलों में क्षमता नरिमाण के लिये आवश्यक सहयोग देता रहा है। भारत चूँकि इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पर अग्रणी माना जाता है, इसलिये भारत कर संबंधी मसलों में दक्षिण-दक्षिण सहयोग अथवा विकासशील देशों के बीच सहयोग सुनश्चिति करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है।

चीन-भारत डजिटल सहयोग प्लाजा की शुरुआत

कृत्रमि बुद्धमिर्ता (Artificial Intelligence) आधारति एकल प्लेटफॉर्म पर भारतीय आईटी कंपनयिओ और चीन के उद्यमों को एक-दूसरे के और करीब लाने वाली पहल चीन-भारत डजिटल सहयोग प्लाजा (Sino-Indian Digital Collaboration Plaza-SIDCOP) की हाल ही में शुरुआत की गई। यह गुइयांग और डालियान की नगरपालिका सरकारों (Municipal Governments of Guiyang and Dalian) के साथ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (National Association of Software and Services Companies-NASSCOM) की एक साझेदारी है। एक भारतीय और एक चीनी कंपनी के संयुक्त उद्यम को इस प्लेटफॉर्म के संचालन की ज़मिमेदारी सौंपी गई है।

गौरतलब है कि भारत के IT उद्यम जटलि कारोबारी माहौल में वभिन्न IT टूलस का उपयोग कर कारोबार में बदलाव लाने और परचालन को अनुकूल बनाने में अपनी वशिषज्जता के लिये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भारतीय IT उद्यमों के ऐसे अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की लंबी सूची है, जिनके कारोबार में बदलाव लाने और बदलते समय के साथ उनके वैश्वीकरण में भारतीय IT उद्यमों ने काफी मदद की है। SIDCOP एक सीमा वहीन मार्केटप्लेस है, जो चीन के उद्यमों को यह अवसर उपलब्ध करा रहा है, ताकि उनके परचालन को अनुकूल बनाने और कारोबार से जुड़े समाधानों में सर्वोत्तम औद्योगिक तौर-तरीकों या प्रथाओं को अपनाने में उनकी मदद की जा सके। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग भारत के शीर्ष समाधान प्रदाताओं (Solution Providers) के साथ जुड़ने और चीनी उद्यमों द्वारा अपनी परयोजनाओं के लिये उपयुक्त समाधान प्रदाताओं की सेवाएँ लेने में कयि जा सकता है।

कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार की वदिश नीतिके तहत वदिशों में भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिकि वसितारति रही। इसके अलावा, सांस्कृतिकि कूटनीतिकि भूमिका बढ़ी और भारत ने सामान्य हतितों को अपने लाभ के लिये उपयोग करने में अधिकि सक्रयिता दखिाई। भू-राजनीतिकि गतशीलता में बदलाव के साथ कदमताल करने में भी भारत की वदिश नीति पीछे नहीं रही। रूस और अमेरिका के साथ संबंधों में सहजता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।